Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 11-08-2006
Participants : Swain Shri M.A. Kharabela,Gulshan Smt. Paramjit Kaur,Kumar Shri Shailendra,Kusmaria Dr. Ramkrishna,Jindal Shri Naveen,Panda Shri Brahmananda,Khan Shri Sunil,Gamang Shri Giridhar,Verma Shri Ravi Prakash,Rawale Shri Mohan,Oram Shri Jual,Owaisi Shri Asaduddin,Gao Shri Tapir,Yerrannaidu Shri Kinjarapu,Chhewang Shri Thupstan,Chidambaram Shri P.

an>

Title: Discussion on the Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2006-07.

SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): Mr. Deputy-Speaker Sir, I wish to thank you for the opportunity given to me to speak on the Supplementary Demands for Grants.

I rise to support the Supplementary Grants for Grants presented by the hon. Finance Minister. Because of the pragmatic and growth-oriented policies pursued by our hon. Finance Minister, under the able guidance of our acclaimed economist Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and the vision of our dynamic Chairperson of UPA, Shrimati Sonia Gandhi, our country has achieved a very high growth rate of 7 to 8 per cent. In the years to come, I am sure, we can achieve even 10 per cent growth rate.

For that, I would like to suggest that we will have to focus more importantly on manufacturing. To do that, I would like to suggest through you to the Finance Minister and to the Government that we need to curb the export of ore, specially iron-ore. If we compare our ore reserves with other countries rich in iron-ore like Ukraine and Australia, we can find that per capita reserve in Australia is 2000 tonnes per person and in Ukraine, it is 1400 tonnes as per its population. In India, it is only 21 tonnes. At the rate at which we are consuming iron-ore and specially exporting iron-ore with 15 per cent growth rate every year, in 20 to 25 years, our iron-ore reserves would be depleted. Even though we say that we have 23 billion tonnes of iron-ore, nearly 10 billion tonnes out of that is magnetite ore found in the Western Ghats. Environmentally, it is a very sensitive area and this ore cannot be used. That is why, I would really urge the Government that in a phased and planned manner, we have to reduce the export of iron-ore and increase the production of steel in our country so that our country as a whole will benefit much more from that.

My second point and the one which is very close to my heart and the hearts of the people is about sports. … (*Interruptions*)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : सर, यह अंग्रेजी में बोल रहे हैं, इन्हें हिन्दी में बोलना चाहिए, अंग्रेजी हमारी समझ में नहीं आती।

श्री नवीन जिन्दल : ठीक है, मैं हिन्दी में बोलता हूं। हमारे देश में खेल बहुत नेग्लैक्टिड हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे देश में खेलों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जब हम ओलम्पिक में जाते हैं और कहते हैं कि हमारा एक बिलियन से ज्यादा लोगों का देश है, हमारे देश की आबादी सौ करोड़ से ज्यादा है और वहां हम एक ब्रौन्ज या सिल्वर मैडल जीत कर आते हैं तो मैगजीन्स के फ्रन्ट पेज पर रिपोर्ट आती है। लेकिन इसके बावजूद हम कुछ नहीं करते। मैं कुछ सुझाव देते हुए अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में कोई ठोस कदम उठाये। यदि सरकार के पास स्पोर्ट्स के लिए कुछ करने के लिए प्लान हो तो ठीक है, अन्यथा मैं जो सुझाव दे

रहा हूं, उन्हें जरूर लागू किया जाए, ताकि सौ करोड़ लोगों के देश भारत को मैडल जीत न पाने के कारण पूरे विश्व के सामने शर्मिन्दा न होना पड़े। आज देश का मान बढ़ाने का यही एक अच्छा माध्यम रह गया है। पहले जमाने में एक देश दूसरे देश को जीतकर वहां अपना झंडा फहराता था, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल एक देश दूसरे देश में जाकर जब खेलों में जीतता है, तभी वह उस देश में अपना झंडा ऊंचा फहरा सकता है। इससे पूरे देशवासियों में एक गर्व की भावना आती है और आप सभी ने भी उस भावना को अनुभव किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि स्पोर्ट्स का बजट बहुत कम है। 1984 के बाद से चाइना ने 286 मैडल जीते हैं और हमने केवल तीन मैडल जीते हैं। यदि हम आने वाले ओलम्पिक्स 2008 या 2012 की बात करें, तो हमने इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं, जिनके फलस्वरूप आगे आने वाले ओलम्पिक्स में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सरकार का स्पोर्ट्स के लिए बजट में करीब चार सौ से पांच सौ करोड़ रुपये का प्रावधान है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसे बढ़ाकर कम से कम दो हजार करोड़ रुपये किया जाए। यदि सरकार स्पोर्ट्स के बजट को नहीं बढ़ा सकती, तो कम से कम जो कंपनियां, चाहे वे पब्लिक सैक्टर में हों या प्राइवेट सैक्टर में हों, यदि वे ओलम्पिक के लिए पैसा देना चाहें, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्रिकेट के पास पहले से ही बहुत पैसा है, अगर ओलम्पिक स्पोर्ट्स के लिए कोई कंपनी पैसा देना चाहे तो 200 प्रतिशत की टैक्स में उसे एग्जेम्पशन दी जाए। सौ प्रतिशत की टैक्स में एग्जेम्पशन आज भी दी जा रही है लेकिन कोई भी कंपनी आगे बढ़-चढ़कर हिस्सा नहीं ले रही है। ओलम्पिक स्पोर्ट्स के लिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा, चूंकि वर्ा 2010 के अंदर हम कॉमन वैल्थ गेम्स ऑरगेनाइज कर रहे हैं और 6000 करोड़ रुपये हम इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलप करने पर लगाएंगे। लेकिन अगर स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग के ऊपर 300 करोड़ रुपये भी नहीं लगाएंगे और कॉमन वैल्थ गेम्स पर 6000 करोड़ रुपये लगाएंगे और हमारे स्पोर्ट्स मैन अच्छा नहीं करेंगे तो इससे हमें भी बहुत शर्मिन्दगी होगी और इसके जिम्मेदार भी हम ही होंगे। मैं खुद भी एक स्पोर्ट्समैन हूं। इसलिए मैं स्पोर्ट्समैन की तकलीफें जानता हूं और यदि फिर भी मैं उन बातों को सदन में नहीं उठाता हूं तो मैं अपने आप से विश्वासघात करूंगा। इसलिए मेरा सरकार से और खास तौर से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि जो कंपनी स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन दे, उसे 200 प्रतिशत की टैक्स में एग्जेम्पशन दी जाए।

दूसरा मुद्दा जो हम चाहते हैं कि हमारे स्पोर्ट्समैन शूटिंग के अंदर मैडल लाएं, जैसे अभी पीछे कॉमन वैल्थ गेम्स जो हुए थे, उसमें हमने पचास मैडल जीते और पचास में से 26 मैडल शूटिंग के अंदर ही जीते हैं। इसलिए मैं सुझाव देने जा रहा हूं कि सरकार का इसमें पैसा भी नहीं लगेगा। मैं कहना चाहता हूं कि शूटर्स की जितनी तकलीफें हैं, उनको ही सरकार अगर मिटा दे तो मैं समझता हूं कि शूटिंग के अंदर हमारे देश के शूटर्स विश्व के सबसे अच्छे देशों से भी शूटिंग में आगे आ सकते हैं। इस अर्जुन की धरती के अंदर, क्योंकि हमारे देश का इतना पोटेंशियल है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर बोलें और अब अपनी बात समाप्त भी करें।

श्री नवीन जिन्दल : महोदय,एयरगन्स के अंदर 37 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी मिलाकर है। जो मैंने पत्र लिखा था, उसका मुझे जवाब मिला है कि डॉमैस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटैक्ट करने के लिए यह ड्यूटी लगाई गई है। डॉमैस्टिक इंडस्ट्री जो एयरगंस बनाती है, उसे कोई भी शूटर नेशनल लैवल पर भी इस्तेमाल नहीं करता। जो एयरगन इंडिया में बनती है, उसकी कीमत 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक है और जो इंटरनेशनल लैवल की एयरगन बनती है और जो शूटर्स इस्तमेल करते हैं, उसकी कीमत एक लाख रुपये है। इसलिए हमें नेशनल शूटर्स को प्रोत्साहन देना चाहिए। अभिनव विन्द्रा और अंजलि भागवत जैसे सैकड़ों शूटर्स हमारे देश में पैदा हो सकते हैं लेकिन हम उनकी मदद नहीं करते। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम उनकी मदद करें लेकिन कम से कम, उन पर जो 35 प्रतिशत हम ड्यूटी चार्ज करते हैं, उसको हम बंद कर दें और उसका आयात आराम से हो सके जिससे` स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर एयरगंन से प्रैक्टिस करके अच्छे शूटर्स बन सकते हैं। इस प्रकार मैं समझता हूं कि हम सभी को गर्व होगा जब शूटर्स इंटरनेशनल लैवल पर जीतेंगे। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार इस पर कोई न कोई कदम अवश्य उठाए और स्पोर्ट्स की पर्फार्मेंस यदि खराब होगी तो हम ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much. In this Supplementary Demands for Grants, the net cash outgo is going to be Rs. 8,668 crore. An amount of Rs. 1,500 crore has been set aside for additional subsidy on imported urea, while Rs. 600 crore has been allocated towards *ad hoc* concessions on fertilizers, taken out of the Government control.

The Finance Minister, in his initial speech, has made a comment that this is not going to impact the fiscal and the revenue deficits. How did he say so? Why did he not factor in the net out go of Rs. 8,668 crore in the Budget? Why did he not anticipate it at that time? Now, he says that there is not going to be any fiscal or revenue deficit. How can we believe that? He has said that the fiscal and the revenue deficits will be within the targeted levels. *The Economic Times*, which is the leading financial newspaper of this country, has published a news item[r14]. It says that during the first quarter of this fiscal, the projected deficit is now 52 per cent. Out of the projected fiscal deficit, now the fiscal deficit has reached 52 per cent mark within the first three months of this year. Is it not going to impact the inflation? How can the hon. Minister of Finance say that it is not going to impact the price rise and the inflation? I say here is a failure and mostly at the end of this year, we will find that the fiscal deficit target has been exceeded. It is very natural that this is going to happen. Take, for example, the fiscal policy of this Government. All the time the hon. Prime Minister and the hon. Minister of Finance of this country including the Deputy Chairman of the Planning Commission say that they are great votaries of reforms. But where is the reform? I mean to say that this Government has been struck by a Left paralytic stroke. This is a lame-duck Government, incapable of taking any decision.

You take the example of disinvestment of ten per cent of the Government shares in NALCO and Neyvelli Lignite Corporation. The Cabinet took the decision, but then they had to roll it back. It is a very strange thing that this Government takes a decision in the Cabinet and then it starts negotiations with their allies. It starts private negotiations and ultimately they say that whatever decision we take in the Cabinet, we are going to roll it back. If it is not a paralytic stroke then what is it? This Government is incapable of taking a single decision independently.

I will give you another example. I am a Member of the Standing Committee on Finance. Since one year the Pension Funds Regulatory and Development Authority Bill has been approved by the Standing Committee on Finance. The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings and Financial Institutions Laws (Amendment) Bill has already been approved by the Standing Committee on Finance. But this helpless Government is incapable of just piloting these Bills in this House because the Left Parties are opposing them. Now, I will give you a suggestion. There is no need for any Committee. You dissolve all these Committees. Now, you form some Committee and include Members only from the Left Parties because now this entire nation is running on the mercy of the Left Parties . In the Standing Committee of Finance all the Members, excepting only one or two Members, have approved these Bills. But this Government is incapable of piloting these Bills. I am asking what is the meaning of democracy. Democracy is the rule of majority. The vast majority of this House had approved these Bills, but the Government is surely been blackmailed, being blackmailed by their own allies. … (*Interruptions*)

SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Sir, I am on a point of order. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order. Nothing will go on record except the speech of Shri M. Kharabela Swain. Please sit down.

(Interruptions) ...*

---

* Not Recorded

SHRI KHARABELA SWAIN : Only one or two Members of the Committee had objected to it. The Government has fallen flat and it is incapable of bringing these Bills in this House. Then, what was the need of sending them to the Standing Committee on Finance, if you have no intention of piloting these Bills? You first negotiate with your allies, if they agree, then you send them to the Standing Committee. Why should we spend so much of time on deliberating on this[R15]? For one year we deliberated on this and made certain very good proposals. So, I do not think that this Government has got any right to say that they want to rule over this country.

Sir, take the example of rise in prices of petrol and diesel. Out of the total cost of petrol and diesel, 52 per cent is tax of various kinds like customs duty, central excise and sales tax levied by State Governments. The hon. Finance Minister was asked as to why he does not put some *ad valorem* duty on it and he goes on simply increasing the tax proportionately. He was asked as to why he is not reducing those taxes. The answer given by the hon. Finance Minister was that it was factored in the Budget. This means, even when the price was less, he anticipated that one day it will rise and that he will have this much of tax from it. That is why he factored it in the Budget. Why does he do that? It is because he wants to put more money into the populist programmes, the *Aam admi*'s programmes of this Government and he wants to put more money into the National Rural Employment Guarantee Programme which is being tom-tommed as the only programme for the *Aam admi* of this country.

Sir, let us take the example of the previous NDA Government. The NDA Government initiated the Golden Quadrilateral Project, the four-lane National Highway Development Programme. This has considerably been slowed down now. I was expecting that the Minister of Road Transport and Highways would be present here, he was here some time before. He gives statistics that 44 per cent of this National Highway Development Programme has been completed during the period of the present UPA Government. You can ask anybody. Who agrees to this claim? The Golden Quadrilateral

Programme has been considerably slowed down. Who does not know this? You know it and every Member of this House knows it.

The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Sarva Shiksha Abhiyan, Swajaldhara, Annapoorna, Antyodaya, all these programmes were initiated by the NDA Government. What has this Government done? Excepting the National Rural Employment Guarantee Programme, can you tell me a single other programme which this Government introduced or initiated? All these programmes were initiated by the NDA Government and they are simply putting some more money in those programmes.

Sir, even the only programme this Government claim to have initiated is the National Rural Employment Guarantee Programme is also being implemented successfully only in NDA-ruled States. Their own leader, the great sacrificer is very much perturbed that the Congress-ruled States are not implementing their own programmes successfully whereas it is the NDA-ruled States like Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Bihar and Orissa are implementing it. They are all implementing it more successfully than Congress-ruled States. If you go through the media reports, everybody says that and day in, day out this is coming out. The hon. Finance Minister is collecting tax from the cost of petrol and diesel and putting it into the National Rural Employment Guarantee Programme. It is just like robbing Peter to pay Paul. So, I would like to say that this Government has got no moral authority and capacity to take any independent decision.

Sir, I will refer to two or three points about my State before I conclude. I am not going to make a long speech[k16]. Si[Rs17]r, in Orissa, during the time of super-cyclone in 1999, the then Government sanctioned a loan of Rs.57.83 crore for the revival of the small scale industries because they were devastated by the super-cyclone. But actually what happened was that this loan was provided by the IPICOL and the Orissa State Finance Corporation, which did not pass it on to the small scale industries, but adjusted it against its residual balance. So, actually it did not benefit the small scale industries. I appeal, to the hon. Finance Minister – I will also write him a letter and will also meet him in this regard – that this sum of Rs.57.83 crore, which is not a very big amount; there is a booming of revenue collection; and the GDP is growing at the rate of eight per cent, be sanctioned not as a loan but as a grant so that the small scale industries are benefited.

Sir, I have one or two more points and then I will conclude. I would like to know from the Government as to what happened to the setting up of an All India Institute of Medical Sciences at Bhubaneswar. The foundation stone of it was laid by hon. Shri Atal Bihari Vajpayee. Sir, we have raised this two times in the House. Once we have raised it through a Calling Attention Motion and then there was also a question by the former Minister, Shri Arjun Sethi, on this. All the time, the hon. Health Minister was saying: “We are going to initiate; we are going to construct the boundary wall”. I would like to know when is this boundary wall going to come up. I do not understand. This is not only a problem of Orissa but it is a problem of six other States. I will appeal to the hon. Finance Minister to see that initiative in this regard is taken up at a very early date.

Sir, Orissa does not have any IIT. So, the Birla Engineering College in Samabalpur, which is a very backward area but it has got all the infrastructure, should be developed as an IIT. I appeal to the hon. Minister to think of it.

My last point is with regard to the National Institute of Science at Bhubaneswar. I would like to know what has happened to that. The hon. Leader of this House, Shri Pranab Mukherjee, inside this House, and the hon. Prime Minister outside this House, gave commitments to the MPs of Orissa that Orissa will also have a National Institute of Science at Bhubaneswar because we did not have anything of that sort. During the time of NDA Government it was declared that Bhubaneswar will have one National Institute of Science, but now the Government has declared that they will have it in the Eastern Zone and that they will have it in Kolkata. We have no objection to that. Let Kolkata have it. Kolkata is having so many Central institutes, let them have another one. Sir, Orissa is comparatively a backward State, it is a poor State, and the Prime Minister has also committed about it. Now, what we found is that the Prime Minister went to Kolkata, laid the foundation stone in Kolkata, but there is no news about Bhubaneswar. We want that the Government should stand by its word. This is a commitment inside this House. The Prime Minister of this country has also committed it. So, we want that they should declare, as quickly as possible, a National Institute of Science at Bhubaneswar.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री बजट, 2006 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इसके साथ-साथ कुछ बाते भी कहना चाहता हूं। हमारे पूर्ववर्ती माननीय सदस्यों द्वारा बहुत सी बातें कही गई हैं और अखबारों के माध्यम से भी कई बातें कही जा रही हैं। बजट के माध्यम से सरकार की नीतियां झलकती हैं। यह कहा जा रहा है कि देश के आर्थिक विकास की दर 8 प्रतिशत बढ़ गई है। इसमें कई चीजें ऐसी आई हैं जिन पर गौर किया जाना जरूरी है और सप्लीमेंट्री बजट के अवसर पर जब यह चर्चा हो रही है, तो इस अवसर पर हम भी कुछ कहना चाहते हैं। सप्लीमेंट्री बजट की एक भूमिका है जिसके अन्तर्गत देखा जाता है कि योजना आयोग के निर्देशानुसार सरकार का डिलीवरी सिस्टम परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है लक्ष्य पूरे होंगे या नहीं तथा मौसम का असर क्या रहेगा? अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा हिस्सा आता है। इसके अलावा मैनूफैक्चरिंग और सर्विस सैक्टर की बैलेंस ग्रोथ लगातार चल पाएगी या नहीं? डिलीवरी सिस्टम प्रोपर वे में प्रफोर्म कर पाएगा या नहीं। इन सभी पर चर्चा की बहुत आवश्यकता है।

महोदय, अभी इस बात का जिक्र किया गया कि सरकार की नीतियों के कारण मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है और महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम यह देख रहे हैं कि सरकार ओपन मार्किट कम्पिटीशन से बहुत प्रभावित है। पिछले दिनों सदन में महंगाई पर चर्चा हुई थी, तब भी इसका जिक्र आया था कि खुले बाजार की अर्थव्यवस्था से सरकार बहुत प्रभावित है कि उसने समाज के दूसरे तबकों की तरफ ध्यान देना उचित नहीं समझा है। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और उसकी आवाज चारों तरफ सुनाई पड़ रही है। अखबारों और टीवी के माध्यम से लोगों ने अपनी बात कही है। सदन में भी इस पर चर्चा हुई तो यह महसूस हुआ कि हमारा जो पीडीएस सिस्टम है, जो कि आम आदमी के रीढ़ की हड्डी है, उसको सस्टैन करने के कारण इतनी ज्यादा खामियां पैदा हो गयी हैं कि ऐसा कोई राज्य नहीं है, जहां से इस बारे में शिकायतें नहीं आ रही हैं कि पीडीएस सिस्टम में चोरी की गई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि अखबारों और टीवी पर यह आने लगा है कि भूख के कारण मौतें हो रही हैं। एक तरफ काश्तकार आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी के स्वास्थ्य की स्थिति खराब होती जा रही है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम न्यूट्रीशन की प्राब्लम को पीडीएस के माध्यम से सोल्व नहीं कर सके हैं। यह अभी तक अनसोल्व है। मैंने ग्रामीण इलाकों में देखा है कि हमारी ग्रामीण बहनों के बदन में खून नहीं है और आज भी 47 प्रतिशत बच्चे मालन्यूट्रीशन के शिकार हो रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं चल रही है, यह उनका फैल्योर है। उनकी

उचित समीक्षा होनी चाहिए। हम सप्लीमेंटरी बजट के अवसर पर इनका मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारा डिलीवरी सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं।

महोदय, यह मैंने पहले भी सदन में कहा था, जब सरकार ने आर्थिक सुधारों का रास्ता तय किया था। हम आर्थिक सुधारों से असहमत नहीं हैं, लेकिन उसके पहले बहुत बड़े पैमाने पर आपको प्रशासनिक और न्यायिक सुधार लागू करने चाहिए ताकि आम आदमी की प्रोडक्टिवीटी बढ़ सके, अर्थव्यवस्था के अंदर उसका योगदान बढ़ सके।

महोदय, मंत्री जी ने सप्लीमेंटरी बजट में कई मदों के लिए पैसा निकालने की बात कही है। मैं खेती के लिया ज्यादा उत्सुक हूं क्योंकि हिन्दुस्तान की 66 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। मंत्री जी ने यूरिया के लिए सब्सिडी बढ़ाने के लिए अनुदान मांगा है। इस अवसर पर मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कृाि की विकास की बहुत गुंजाइश है, लेकिन आज भी जीडीपी में उसका योगदान ढाई-तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं जा पा रहा है। जबकि इस बात की अपेक्षा की गयी है कि इसे 4-6 प्र ातिशत तक बढ़ जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में खेती पर आप विशेा कार्य करेंगे। इसके अलावा जो छोटा काश्तकार है, हालांकि आपने प्रावधान किया है कि बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से उनको तीन गुणा ज्यादा ऋण उपलब्ध हो। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि ऋण उपलब्ध कराने का काम सही ढंग से चलता तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था का अपेक्षित विकास हो जाता । बहुत आवश्यक तथ्य यह है कि कृाि की अर्थव्यवस्था को बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव इकोनोमी के तौर पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। विशेा तौर पर एक मॉडल, जो दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में अपनाया गया है कि हर गांव को उत्पादन और प्रसंस्करण की एक इकाई बनाने के लिए योजना बननी चाहिए। लो कैपीटल, लो कोस्ट और लेबर इंटेंसिव जो स्माल इण्डस्ट्रीज़ हैं, जो प्रसंस्करण और मैन्युफैक्चरिंग की इण्डस्ट्री है, उसे ग्रामीण क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए विशेा योजना बनाई जानी चाहिए।

मैं फिक्की की वार्षिक आम बैठक में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 दिसम्बर, 2005 की एक स्पीच के विाय में रैफरेंस देना चाहता हूं। उन्होंने खुद भी इस बात पर जोर दिया था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर है, उसका हमारे आर्थिक विकास में जो हिस्सा है, वह केवल 17 परसेंट तक है, लेकिन इसे 25 से 35 परसेंट तक बढ़ाया जाना चाहिए। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो कृाि क्षेत्र है और कृाि पर आधारित जो छोटे उद्योग हैं, विशेा तौर पर ऐसे कारोबार, जिनमें लेबर वर्क ज्यादा है, जो विशेा तौर पर श्रम पर आधारित हैं और छोटी कीमत लगाकर हमारा जो एक कंज्यूमर मार्केट है, जो आगे विकसित हो रहा है, उसमें उनका हिस्सा बढ़ना चाहिए। इस सम्बन्ध में अगर विशेा योजनाएं बनाकर सरकार काम करेगी तो इस बात से आर्थिक विकास में फायदा होगा।...(व्यवधान)

मैं जल्दी कन्क्लूड कर रहा हूं, मेरा भााण बहुत लम्बा नहीं है। जो विकास का एजेण्डा है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है कि हम आर्थिक विकास प्राप्त करना चाहते हैं और हमको आने वाले वर्षों में सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथ कम से कम 12 से 14 परसेंट तक की हर हाल में प्राप्त करनी है और उसके लिए हमारा पूरा जो बजटिंग सिस्टम मकेनिज्म है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वह यह काम कर रहा है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि जब सभी सरकारों के लिए, चाहे वह भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हों, एक संवैधानिक रैस्पोंसिबिलिटी, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी लगाई जाये कि आर्थिक विकास की एक निश्चित दर कम से कम 10 परसेंट या 12 परसेंट की उनको हर हाल में प्राप्त करना लाजिमी कर दिया जाये। अगर ऐसा नहीं कर सकेंगे तो निश्चित सी बात है कि हमारी इकोनोमिक ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं रह पाएगी।

मैं यहां पर एक बात बहुत गहराई से कहना चाहता हूं कि हमने डैमोक्रेटिक सर्वे भी देखे हैं, आज जब पूरी दुनिया उम्रदराज हो रही है, पेंशन लेने की तरफ बढ़ रही है, तब हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत बड़ी तादाद में नौजवान हैं, जो आगे बढ़कर इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। मैं विशेा तौर पर माननीय वित्त मंत्री जी से सप्लीमेंटरी ग्राण्ट्स के अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमने इस सदन के माध्यम से संकल्प लिया है कि हम हर बच्चे को शिक्षित करेंगे और हिन्दुस्तान के लिए एक एफीसिएंट मैनपावर हम आगे जाकर बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक जो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकर बन गया है, उसके बावजूद भी हम कानून नहीं बना पा रहे, जिसके माध्यम से हम हर बच्चे को लाजिमी तौर पर शिक्षित करें। ...(व्यवधान)

मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। बहुत छोटा सा हिस्सा रह गया है, आप मुझे मौका दीजिए, यह बहुत आवश्यक है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर 45 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की रकम जनता खर्च करती है। करीब 2-3 लाख बच्चे हिन्दुस्तान से बाहर पढ़ रहे हैं। उच्च शिक्षा की जो स्थिति है, मैंने आपको बताया कि बहुत चिन्ताजनक स्थिति है। आज भी हमारे यहां करीब आठ करोड़ छात्र-छात्राएं, जो इण्टर पास कर रहे हैं, 10 + 2 पास कर रहे हैं, उनमें से केवल 6 परसेंट लोगों को ही उच्च शिक्षा में एक्सेस मिल रही है। यह बहुत चिंता का विाय है। इन 6 प्रतिशत लोगों में भी 72 प्रतिशत छात्र-छात्रायें आर्टस के स्टूडेंट्स हैं और केवल 28 प्रतिशत मेडिकल या टेक्नीकल एजुकेशन और दूसरे क्षेत्रों के हैं। आज इस बात की जरूरत है कि बजट के माध्यम से भारत सरकार बहुत बड़ी तादाद में उच्च शिक्षा के इन्स्टीटयूट खोले, जिसमें रिसर्च और डेवलेपमेंट के अल्ट्रामार्डन इन्स्ट्रूमेंट्स उपलब्ध हों, जिससे बड़े पैमाने पर हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिन्दुस्तान के नौजवानों को शिक्षित करके उनको अर्थव्यवस्था की एक सक्षम इकाई बना सकें। रोजगार एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हम हिन्दुस्तान के नौजवानों को बड़ी तादाद में रोजगार दें। मैं के वल इतना कहना चाहता हूं कि कृाि क्षेत्र पर विशेा ध्यान देने का काम करें और साथ ही मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर पर भी ध्यान देने का काम करें। इन दानों में एक रिश्ता है, मैं सप्लीमेंटरी बजट के माध्यम से इस बात का अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में सरकार ऐसे कदम उठाए कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो नौजवान पढ़-लिखकर तैयार हों वे अपने पैरों पर खड़े हों और हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने का काम करें।

श्री मोहन रावले : महोदय, महाराट्र में अभी जो फ्लड आयी, उसके संबंध में प्रधानमंत्री जी से शिवसेना के लोग मिले थे। वहां के लिए जो पैकेज दिया गया है, वह बहुत कम है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम एक हजार करोड़ रूपया महाराट्र को दिया जाए। वहां क्या हालत है मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहता हूं...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: No running commentary, please.

श्री मोहन रावले : प्रधानमंत्री के विदर्भ और मराठवाड़ा में जाने के बाद भी हमारे क्षेत्र में किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं। ये आत्महत्यायें और भी जगहों पर हो रही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने ज्यादा कर्ज नहीं दिया है, आप देश का भला देखिए, अगर देश में लोग होंगे तभी देश का भला हो सकता है लेकिन किसान मर रहे हैं, किसानों को पचास हजार या एक लाख रूपया कर्ज दिया गया है, अगर आप वह माफ कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे किसान आत्महत्या से बच सकते हैं। इनकी सरकार ने एलान किया था, जब महाराट्र की सरकार आयी थी, तो ऊर्जा मंत्री ने ऐलान किया था कि हम ऋण माफ कर देंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे सब भूल गए। कांग्रेस वायदे करना जानती है लेकिन उसे निभाना नहीं जानती। वहां आत्महत्याएं हो रही हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का लोन माफ कर दीजिए।

मुंम्बई में बम ब्लास्ट हुआ और इसमें जो आरडीएक्स आया, वह हवाई मार्ग से आया होगा या जमीन से या पानी के रास्ते से, जहां तक मेरी जानकारी है, उसके मुताबिक वह कंटेनर से आया। कल भी दिल्ली में आरडीएक्स मिला है, यह कहां से आता है? कस्टम के लोग क्या कर रहे हैं? यह कस्टम के थ्रू ही आया होगा। कस्टम के लोगों द्वारा क्या निगरानी हो रही है? इसके ऊपर आप ि वशेा ध्यान दीजिए, नहीं तो करोड़ों की हानि हो जाएगी। पैट्रोल के बारे में इन्होंने बात कही है। महाराट्र में एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। ...* उन्होंने बायो-डीजल के क्षेत्र में बहुत रिसर्च की है। अगर हम बायो-डीजल लगाएंगे और किसानों को अवेयर करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नाम लेना अवाइड करिए।

* Not Recorded

श्री मोहन रावले : मैं उनकी सराहना कर रहा हूं। She is the Principal Secretary in the Maharashtra State. मै किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं कि हमारे यहां दस करोड़ किसान हैं, अगर हम उनमें अवेयरनेस करेंगे, तो वहां बायो डीजल हो सकता है। जट्रोफा वनस्पति हम अगर लगाएंगे, तो वह तीन साल में पूर्ण हो जाएगी और तीन सालों में इतना बायो डीजल मिल जाएगा कि मेरी जानकारी के मुताबिक पांच सालों में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकेंगे। स्वैन जी बोल रहे थे कि डीजल बहुत मंहगा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे पेट्रोल के दाम भी कंट्रोल में आ सकते हैं। महाराट्र में रिसेंट रिसर्च हुयी है और पेटेंट मिला है। हम प्लास्टिक से भी पेट्रोल बना सकते हैं। एक किलो प्लास्टिक से अगर हम पेट्रोल बनाएंगे, तो 80 प्रतिशत पेट्रोल मिलता है, 10 प्रतिशत कोक मिलता है और 10 प्रतिशत गैस मिलती है इसे पेटैंट मिला हुआ है। अगर सरकार उस ओर ध्यान देगी तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा। मैं पूरे देश के किसानों के लिए बोल रहा हूं।

कोस्टल एरियाज़ जैसे केरल, अंडमान, निकोबार, महाराट्र, कोंकण, उड़ीसा आदि में जटरोफा का उत्पादन बहुत ज्यादा हो सकता है। जटरोफा से बायो-डीज़ल बन सकता है। जैसे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इंडियन ऑयल की कॉलटेक्स, बर्माशैल और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ओएनजीसी जैसे स्वतंत्र कार्पोरेशंस की स्थापना की गई थी, यदि सरकार वैसा ही कार्पोरेशन बायो-डीजल के लिए बनाए तो उससे किसानों में अवेयरनैस आएगी। अगर हर राज्य को दो सौ से तीन सौ करोड़ रुपये दे दिए जाएं तो मुझे लगता है कि हम खुद पैट्रोल और बायो-डीजल का उत्पादन कर सकते हैं।

मुम्बई शहर में हर रोज पांच हजार से दस हजार लोग बाहर से आते हैं। वे वहां गंदगी पैदा करते हैं। इससे ड्रेनेज, पानी, बिजली आदि का बोझ मुम्बई शहर पर पड़ता है। मुम्बई से 71,773 करोड़ रुपये सालाना टैक्स के रूप में केन्द्र को रिवेन्यू मिलता है, लेकिन मुम्बई को क्या मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि मुम्बई को उसका दस प्रतिशत यानी सात हजार करोड़ रुपये सालाना मिलने चाहिए। हम मुम्बई से आते हैं, लेकिन हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है। मुम्बई को नैगलैक्ट नहीं किया जाना चाहिए।

मुम्बई शहर में एक करोड़ 25 लाख से एक करोड़ 50 लाख तक की आबादी है जिसमें 75 लाख लोग झोंपड़-पट्टी में रहते हैं। उनके रीहैबीलिटेशन के बारे में कुछ किया जाना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी, तब उसने झोंपड़-पट्टी के लोगों को लिए मुफ्त घर देने की योजना बनाई थी।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address to the Chair and not to the individual Member.

SHRI MOHAN RAWALE : All right.

मेरे पास श्री चंद्रकान्त खैरे बैठे हुए हैं। वह वहां गृह निर्माण मंत्री थे।...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, मुम्बई को कम से कम सात हजार करोड़ रुपये सालाना मिलने चाहिए।

मैं बैंकों के बारे में कहना चाहता हूं कि उनकी मोनोपली है। हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को ही बैंकों से ऋण दिया जाता है, लेकिन यदि कोई बेरोजगार युवक लोन लेने जाता है तो कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे टाल दिया जाता है। श्री वर्मा

ने नौजवानों के बारे में कहा। बेरोजगार युवकों को किस काम के लिए पैसा मिल सकता है, इस बारे में अवेयरनैस कराई जानी चाहिए।

इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स के बारे में कहना चाहता हूं। श्री जिंदल ने इस बारे में बहुत अच्छी बातें कहीं, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। कॉमनवैल्थ गेम्स में जिन लोगों को मैडल मिले हैं, मैं उन्हें भी बझाई देना चाहता हूं। उस वक्त मैं आस्ट्रेलिया गया था। कुमारघाट के मंजुनाथ फरताड़े के पिता किसान हैं।

14.00 hrs.

उसे शूटिंग में 600 में से 596 प्वाइंट्स मिले हैं। अगर हम ओलम्पिंक में मैडल प्राप्त करने के लिए नजर रखते हैं, तो अच्छे खिलाडियों को आगे लाने के लिए हमें पैसों से मदद करनी चाहिए। उनके लिए हमें कस्टम ड्यूटी माफ करनी चाहिए। सरकार द्वारा उनकी मदद करनी चाहिए। यह देश 100 करोड़ लोगों का है लेकिन हमें एक भी ओलम्पिक मैडल नहीं मिलता। यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात है। मैं खुद स्पोर्टसमैन हूं इसलिए मैं ऐसी बात कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिंदल जी ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि इस मंत्रालय को 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और वह पैसा स्पोर्ट्समैन के पास जाना चाहिए। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बायो-डीजल के प्रति लोगों में अवेयरनैंस पैदा की जानी चाहिए और किसानों को आत्महत्या करने से बचाना चाहिए।

मैं अभी काफी कुछ बोलना चाहता था लेकिन समय नहीं है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BRAHMANANDA PANDA (JAGATSINGHPUR) : Hon'ble Deputy Speaker, Sir, I thank you for allowing me to participate in the discussion on the Supplementary Demand for Grants. The aim of our Budget is to fulfill the aspirations of a resurgent, prosperous India. The UPA Govt. has expressed its commitment to the welfare of the common man through programmes like Bharat Nirman, Rural Employment Guarantee Scheme, etc. However, it is most unfortunate that prices of essential commodities have escalated beyond imagination. The common man is finding it very difficult to survive. Hon'ble Finance Minister is here. He should understand that after fifty eight years of Independence, if the common man has no access to basic essentials, it is a very sad commentary on the state of affairs. The plight of the common man is unimaginable.

Sir, I come from Orissa which is frequently ravaged by natural calamities like flood, cyclone or drought. It is, in fact the capital city of India as far as natural disasters are concerned. Population of Orissa is dominated by Schedule Tribes and Scheduled Castes. About 47.13% of the people live below the poverty line. Our late Chief Minister Biju Patnaik had dreamt of an India where there will be no regional imbalance. Every state of India will be equal partners in prosperity. But, unfortunately, his dreams remain unfulfilled. Orissa remains a backward State. Despite being filled with rich deposits of minerals, forests and beautiful temples, this State languishes in poverty. We have huge deposits of iron ore, coal and manganese and we contribute the nation's wealth substantially. Orissa is a milestone in the nation's road to prosperity. However, we do not get the credit we deserve. We have no share in the coal royalty or the revenue of the Centre. It has been a long pending demand of Orissa to be given a special

---

*English translation of the speech originally delivered in Oriya

category status. But that has not happened so far. Eight States of India have been given special financial packages but not Orissa. Orissa continues to be a victim of regional imbalance and Centre's neglect.

Every Budget makes some provision for the betterment of agriculture and agriculturists. But in our country the farming community remain at the receiving end. They do not get loans, have no access to irrigation facilities or agricultural implements. They live in poverty and forced to commit suicide. In Orissa too the farmer's condition is pitiable because of Centre's apathy. However, the present Chief Minister Mr. Naveen Patnaik has understood the problem and is giving adequate thrust to this sector. He has initiated an agro-industrial revolution to bring Orissa at par with other progressive States.

Sir, earlier my esteemed colleague from Baleswar was mentioning about National Science Centre. It is really very unfortunate that the Govt. is employing delaying tactics about this important issue. When we had met the Hon'ble Prime Minister, he had assured us that he will take initiative to establish National Science Centre at Bhubaneswar. So far we have got only empty assurances. Their translation into reality remains a question mark.

Similarly, we are awaiting justice with regard to the establishment of AIIMS. We have been told that land is being acquired. Hob'ble Deputy Speaker, Sir, I want to draw your attention that a State like Orissa continues to be neglected by the Centre. We are in a debilitating state because of the onslaughts of natural calamities. Hence, the Centre should extend a helping hand. It is most unfortunate that the KBK districts of Orissa have been excluded from the 11th Five Year Plan. The people of these districts continues to languish in abject poverty. Their standard of living is abysmally low. There should be a special scheme for these people. Sir, at present Orissa is inundated by flood in the districts of Malkangiri, Jaipore, etc. Incessant rain has thrown normal life out of gear. In many parts of the State flood has caused serious damage to crops and lives. I have no complain if other States manage to get special financial packages. But Orissa should not be neglected and deprived of its rightful claim. The Centre should announce a special relief package for the flood affected areas.

I have already spoken about the plight of farmers and unemployed several times in the past. We should have a concerted effort and planned approach to solve problems. Otherwise, all these discussions on Demands for Grants will be futile. Every year we will pass them in this august House and crores of rupees will be spent but it will not benefit the poor masses.

I belong to Orissa, the land of Lord Jagannath, who is known for his humanitarianism. I appeal to the Centre to do justice to this holy State.

SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN (BHATINDA) : Thank you, Deputy-Speaker, Sir, for the opportunity given to me to speak on the Supplementary Demands for Grants (General), in my mother-tongue Punjabi. Sir, every year, we pass the General Budget in the Parliament. It is an annual feature. However, the budget has a tremendous impact on the lives of common man in both, urban and rural areas. The last year's budget has left Punjab high and dry.

The budget had a devastating effect on the industries in Punjab. Our neighbouring states were given special packages. As a result, there was a flight of industries from Punjab to the neighbouring states. No financial assistance was given to Punjab. No relief measures were announced for Punjab. There was no reduction in custom duties or excise duties. So, the industrialists shifted their industries to neighbouring states in search of greener pastures. As a result, the industry sector in Punjab is in shambles today.

In 1999, the NDA Government had announced the setting up of a refinery in Punjab at a cost of Rs. 14,000 crores. However, it has not yet seen the light of the day. No one knows whether this plant

will ever materialize.

Sir, the farmers in Punjab are in a miserable condition. Special packages were announced for the farmers of various states. But the Government turned a deaf ear to our demands for bailing out the farmers of Punjab. Over 2000 farmers have committed suicide in Punjab. But the Central Government has meted out step-motherly treatment to Punjab. Its genuine demands have been ignored. No compensation has been granted to the suffering farmers of Punjab. Entire families of farmers have committed suicide due to abject poverty and disillusionment.

---

*English translation of the speech originally delivered in Punjabi

Recently, the Government increased the MSP for food-grains by just Rs. 10. This was a cruel joke played upon the farmers of not only Punjab, but of the entire country. The farmers provide us food-grains. Punjab contributes in the central pool in a big way. However, the farmers of Punjab are leading a life of misery and they have been left to fend for themselves.

Hence, I appeal to the Hon. Finance Minister to come to the rescue of farmers of Punjab and provide aid and succour to them. The Government needs to rectify its wrong policies to stop the farmers from committing suicide.

Sir, the health facilities in Punjab, both in the urban and rural areas, show a dismal picture. The health infrastructure is also in shambles. Neither doctors, nor medicines are available in Government hospitals. Hundreds of posts of doctors are lying vacant in these hospitals. Generally, the rich and affluent people visit private hospitals for medical treatment, It is only the poor people who visit Government hospitals. The hospitals in rural areas and mofussil towns are bereft of doctors and medicines. The poor people cannot get medical treatment in these hospitals. The need of the hour is to improve the infrastructure in the health sector in Punjab.

The education sector in Punjab is also in a mess. Crores of rupees are being spent on various schemes like ‘Sarv Shiksha Abhiyan’ , ‘Mid-day meal’ and ‘Anganwadi’ but without any tangible result. 70% schools in Punjab are without teachers or principals. Posts of teachers are lying vacant in these schools. The development of a nation is directly linked to education. It is enshrined in the constitution that the children should be imparted free and compulsory primary education. However, the drop-out rate of children in the schools is over 80%. Potable water is not available in these schools.

Many school-buildings are in a dilapidated condition. Basic infrastructure is missing in these schools. This dismal scenario must improve.

Sir, poverty is on the rise throughout the country. The common man is finding it difficult to make both ends meet. Out of abject poverty and sheer disillusionment, entire families are committing suicide. Prices of essential commodities have sky-rocketed. We hold discussion in the House on the subject of poverty. But, the ground-reality remains dismal for the poor man. Pulses are being sold at Rs. 60 /- per Kg. As a result, the common man is suffering. So, I appeal to the Hon. Finance Minister to take steps to bring down the prices of essential commodities immediately.

Sir, we talk about a 7% to 8% growth rate which is considered healthy for our economy. However, in reality, this development or growth is nowhere to be seen in our towns and villages. A lot of schemes have been announced by the Government for the welfare of poor people hailing from villages. But, these schemes never reach the needy. The PDS system should be improved so that the poor people may reap its benefit. Schemes for BPL families are floundering. Genuine people have been dropped off the list of BPL families whereas bogus people have managed to get their names included in the BPL list. All these shortcomings should be removed. Corruption has been the bane of these schemes. Corrupt officials must be punished. I urge upon the Hon. Finance Minister to order a fresh survey of BPL families so that the truth comes to light and genuine people get the benefit.

Sir, in the villages, roads are in a bad condition. They are full of potholes. Under the 'Pradhan Mantri Gramin Sarak Yojna', funds should be granted to the states so that repair of these roads can be undertaken.

Unemployment is on the rise. In Punjab, 40 lakh youths are unemployed. Only one district of Punjab has been included in the 'Pradhan Mantri Guarantee Rozgar Yojana'. These unemployed youths fall a prey to drugs. Hence, I appeal to the Hon. Finance Ministry to announce schemes that can generate employment. Only then can we save these youths from going astray.

Sir, in the villages, clean and safe drinking water is not available. Efforts should be made to install water treatment plants that can provide clean and safe drinking water to the villagers.

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़) : उपाध्यक्षमहोदय, आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य), 2006-2007 पर होने वाली आम चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान कुछ वियों की ओर आकर्ति करना चाहता हूं। यूपीए सरकार आने के पूर्व आम आदमी के लिए काम करने की सौगंध ले कर आई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद आम आदमी के रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजों, जैसे दाल, चावल, आटा, कैरोसीन आदि के दाम इतने बढ़ गए हैं

कि उससे आज हर व्यक्ति परेशान है। मैं गांव में घूमता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आज इतना प्राइस राइज क्यों हो रहा है - मैंने कहा कि मुझे तो पता नहीं, आप ही बताइए। लोगों का कहना है कि शायद वोल्कर कमेटी का परिणाम है। पेपर में निकला था कि हमारे पड़ोसी राट्र, पाकिस्तान और बांग्लादेश में डीजल और पेट्रोल की कीमत कम है, हमारे यहां ज्यादा क्यों है, इसका क्या कारण है? इस बारे में माननीय वित्त मंत्री जी को विचार करना चाहिए। माननीय सदस्य श्री स्वाईं बता रहे थे कि इसका 52 परसेंट भाग विभिन्न टैक्सों के रूप में सरकार द्वारा लिया जाता है। क्या टैक्स कम नहीं हो सकते हैं? टैक्स क्यों लगा रखे हैं, क्योंकि टैक्स द्वारा कमाए पैसे को हम कहीं और खर्च करना चाहते हैं लेकिन होता है कुछ और। आप जनता की जेब में से पैसा ले रहे हैं, उस पैसे को कहीं और कैसे लगा सकते हैं? माननीय वित्त मंत्री जी को इस बारे में विचार करना चाहिए।

बायो-डीजल के बारे में संभावनाएं एक्सप्लोर करनी चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के यहां एक गाड़ी लगभग एक साल से चल रही है और वह गाड़ी बायो डीजल से चलती है। मैं सोचता हूं कि भारत के जितने राज्य हैं, उनमें से बायो-डीजल के प्रयोग में किसी राज्य ने अगर प्रगति की है, तो छत्तीसगढ़ ने की है। वहां से यह तक न्यूज भी आई है कि इसका रिसर्च वर्क किसी फौरेन कम्पनी को बेच दिया गया है या कोई फौरेन कम्पनी वह रिसर्च वर्क चोरी करने की कोशिश कर रही है। इस बारे में मोहन रावले जी भी कह रहे थे कि क्यों नहीं इस पर पैसा लगाया जाए। आज तेल के लिए इतना झगड़ा हो रहा है। सब तरफ लोग तेल का क्राइसिस झेल रहे हैं। हमारी वित्तीय अर्थव्यवस्था पर तेल प्रभाव डालता है, इसलिए तेल का यदि कोई सही विकल्प हो सकता है, तो व्यापक रूप से जटरोफा की प्लांटेशन करनी चाहिए, उस पर सब्सीडी देनी चाहिए और जटरोफा प्लांटेशन के लिए आम आदमी को बढ़ावा देना चाहिए। जहां बंजर जमीन है और जहां प्लांटेशन हो सकता है, इस दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी को प्रोत्साहन देना चाहिए।

मैं अपने क्षेत्र उड़ीसा की बात आपको बताता हूं। वहां आयरन ओर का रेट बढ़ जाने के कारण ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस इतना बढ़ा है कि एक दिन में एक नेशनल हाईवे पर जहां पहले 1000 से 2000 गाड़ियां चलती थीं, वहीं आज 15000 गाड़ियां 24 घंटे में चलती हैं। इसे लेकर हम परेशान हैं। मैंने मंत्री जी को बताया था, बालू साहब यहां उपस्थित हैं, उन्होंने मुझसे प्रौमिस किया था कि उड़ीसा के सारे नेशनल हाईवेज़ को वे स्ट्रेंथन करेंगे, खासकर दो - नेशनल हाईवे 215 और नेशनल हाईवे 23 को - स्ट्रेंथन करेंगे।

लेकिन उन्हें जितना पैसा देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया है। इन दो प्रोजैक्ट्स के लिए खास तौर पर पैसा दिया जाना चाहिए। इससे हमें लाभ होगा। आज बहुत सी वस्तुओं का एक्सपोर्ट रुका हुआ है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैंने रेलवे के दो-तीन प्रोजैक्ट्स को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए सुझाव दिया था। 98 किलोमीटर का रेलवे प्रोजैक्ट क्योंझर से दइतारी अगर पूरा हो जाता, तो रेलवे का जितना पैसा इनवैस्ट हुआ है, उससे अधिक लाभ हो सकता है। मेरे ख्याल से सरकार अगर कोशिश करे तो दो-तीन महीने में वह प्र ोजैक्ट पूरा होगा। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वित्त मंत्री जी ने बजट में इसके लिए पर्याप्त प्रावधान भी नहीं किया है।

14.26 hrs.

(Shrimati Krishna Tirath in the Chair)

मैं इस बारे में रेल मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से भी मिला था। उनके भााण में भी इस बात का जिक्र आया था कि उसे दिसम्बर 2006 तक चालू कर देंगे, लेकिन यह प्रोजैक्ट अभी तक पैडिंग पड़ा है।

उड़ीसा के कालाहांडी और बोलांगीर जिलों में भुखमरी है। सरकार ने इसके लिए लौंग टर्म एक्शन प्लान बनाया था। इसके लिए एक्सट्रा बजटरी प्रॉवीजन करने से भुखमरी कुछ हद तक दूर हो गई थी। केवीके के लिए स्पैशल प्रोजैक्ट बना था, लेकिन अब सुनने में आया है कि वह भी बंद होने जा रहा है, जो ठीक नहीं होगा। ऐसे में वहां भुखमरी की स्थिति फिर पैदा हो जाएगी। ऐसी न्यूज आती हैं कि वहां बच्चों की बिक्री तक कर दी जाती है। मेरा निवेदन है कि आप इस प्लान को एक्सटेंड कीजिए।

किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में मैं वित्त मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं स्टैडिंग कमेटी के कर्नाटक दौरे के समय स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का रिव्यू करने के लिए गया था। वहां के अधिकारियों ने हमारे सम्मुख प्रैजेंटेशन भी रखा।

उसमें बताया गया था कि वह बैंक पंचायतों तक पहुंच गया है। जब हमने डिटेल में दिए गए आंकड़ों की छानबीन की तो पता लगा कि लोगों को उस बैंक से आसानी से लोन उपलब्ध नहीं होता है। कुछ बड़े-बड़े लोगों को लोन मिल जाता है, लेकिन छोटे किसानों या जो बिजनेस करना चाहता है, उनके लिए बैंक की शर्तें बहुत कठिन हैं। एक-डेढ़ लाख रुपए तक के लोन की शर्तें आसान होनी चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और वह लोन जल्दी मिलना चाहिए।

वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हं कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा एफडीआई आ रहा है, जिससे सभी उत्साहित हैं। मैंने सदन में प्रश्न भी किया था कि अगर एफडीआई लाएंगे, तो उसमें कितने परसेंट उनका पैसा लगेगा और कितने परसेंट मार्किट से लोन उठाया जाएगा। जब मैंने कुछ लोगों से जानकारी ली तो उन्होंने मुझे बताया कि 10-15 हजार करोड़ रुपए बाहर से लेंगे और बाकी इंडियन मार्किट से उठाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसे पुनः देखें।

हमारे यहां आयरन ओर, बॉक्साइट और मैगनीज के भंडार हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील ने इनका एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। वित्त मंत्री और कॉमर्स मिनिस्टर इनका एक्सपोर्ट करना एलाऊ कर रखा है जो तुरन्त बंद होना चाहिए। मैंने इसके बारे में पत्र भी लिखा है। मैं चाहता हूं कि इस पर हमें ध्यान देना चाहिए।

सरकार नाल्को जैसी लाभकारी संस्थाओं का विनिवेश करना चाहती है। उड़ीसा की पाराद्वीप फासफेट लिमिटेड घाटे में जा रही थी, जिससे उसे बेच दिया गया। एक प्राइवेट पार्टी ने उसे खरीद लिया। दो साल बाद फिर सरकार उसे खरीद रही है इस खरीद-बिक्री में बड़ा घपला हुआ है। माननीय वित्त मंत्री जी इसकी छानबीन करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम ि वनिवेश करना चाहते हैं, लाभकारी संस्थाओं का विनिवेश करना चाहते हैं। लेकिन जो संस्था घाटे में गई थी, जिसे एक प्राइवेट पार्टी को बेच दिया गया था, उसे आप फिर खरीदेंगे, यह क्यों हो रहा है?

सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you, Madam. The Indian economy over the last one and a half decades, since the inception of the neo-liberal policies in 1991 has experienced an immense magnitude of inequality. Whether it is the growing disparity in the rural-urban scenario or the increasing inequity in the socio-economic one, the sufferings of the poor in our country seems to escalate at an increasing pace. Since the UPA Government assumed power two years ago, the slogan of growth, stability and equity are the main objectives. Though in our present economic scenario, growth has gained a huge significance, equity has suffered immensely. In this backdrop, I would like to place my views regarding the first proposal of the Supplementary Demands for Grants.

The core philosophy behind placing the Supplementary Demands for Grants is the additional need of expenditure that various Ministries face. Given the immense financial crunch that the social sector allocations faced during the previous NDA Government, the continuous reduction of social sector expenditure till date in the name of fiscal prudence and discipline, in my opinion, is based entirely on wrong assumptions of pre-Keynesian economics. Thus, I heartily support the Demands made by the various Ministries, Departments for additional allocations in those sectors.

The Ministry of Agriculture has made an additional Demand of a meagre sum of around Rs.160 crores. The responsibility of the agricultural sector lies primarily with the State Government. But given the acute agrarian distress that has engulfed the rural India, I believe that the Centre should play an active role in pulling up the agrarian economy. In fact, the recommendations of various Finance Commissions, in particular the Eleventh Finance Commission, have crunched the financial status of the State Governments. So, the additional Demands in the Agricultural sector should definitely be met up with.

Another related sector is the Ministry of Rural Development. The Supplementary Grant required by this Ministry is especially for two reasons. Firstly, the issue of special securities to Food Corporation of India for the settlement of outstanding debts on account of release of foodgrains under SGRY and National Food For Work Programme and secondly, for the pass through of the UNDP assistance for operationalisation of the National Rural Employment Guarantee Act. Both these programmes assume huge importance in the context of the present Indian scenario. As I said earlier, there is immense amount of rural distress. From 2004, we are seeing that many *Adivasi* children have died because of malnutrition and starvation, especially in the Northern and Eastern borders of Maharashtra. My request to the hon. Finance Minister is, to immediately waive all the arbitrary conditions which are in force at present for issuing BPL ration cards and to make these cards available to all those who wish to apply. Universalisation of PDS is the need of the hour.

Hon. Prime Minister went to Vidharbha and announced a package for the farmers of Vidharbha. Despite the announcement of the package, the farmers of Vidharbha are still committing suicides. I would like to know what best the present Government can do because these suicides will have to be stopped. Secondly, my State of Andhra Pradesh has also requested for the same package, on the lines of Vidharbha. It is still pending with the Ministry of Finance. I hope that this package is expedited and is given to the State of Andhra Pradesh.

Technically speaking, in strict economic terms, there is no apparent reason why the Central Government should hesitate in increasing expenditures. The immanent logic of liberalisation pushes governments, no matter what their political complexion, into bowing to the caprices of globalised finance and hence necessarily having to sacrifice welfare objectives. Now there is a chance before the UPA Government to dispel, to prove such critics and detractors wrong. Hence, much more needs to be done for the "*aam aadmi"*.

My last point is regarding the budget for the minority ministries. When the hon. Finance Minister presented the Budget for this year, at that time the Ministry had requested for an equity support of Rs.57 crore for National Minority Development Finance Corporation[R18].

The hon. Finance Minister in his Budget had given the equity support of Rs.18.29 crore to NMDFC. Now in the Supplementary Demands for Grants, he has allocated Rs.16.47 crore. That comes to Rs.34.76 crore but the Ministry of Minorities Welfare had asked for Rs.57 crore. I would request the hon. Finance Minister to increase it to Rs.57 crore.

I am thankful to the hon. Finance Minister for the increase in the corpus for the Maulana Azad Education Foundation to Rs.100 crore, but that is not enough. It has to be increased to at least a minimum of Rs.500 crore. You should increase the corpus fund for Maulana Azad Education Foundation which is doing a significant work by giving scholarship to minority girls. This has to be increased.

Lastly, a sum has been allocated to the Department of Personnel. My point over here is that what steps are the Government taking to ensure that unemployment comes down, especially among the Muslim minorities. In the light of the recent statement of the National Security Adviser saying that the LeT has infected Army and everything, the window of opportunity that was created for the Muslim minorities in the Defence Forces and police force has been shut now for ever because of his one statement. Unfortunately, the previous Government's NSA has never issued such a statement and he has gone to the extent of saying that the Muslims who go for Haj, their background should be checked. I would like to know whether this is the stand of this Government. How can he say such a thing by writing a letter? Now no State Government is willing to take Muslim minorities in police and other Departments of the Forces. In Intelligence Bureau, there are 200 IPS officers. Out of these 200 officers, there are only two Muslim IPS officers. I do not want to name them. You do not have any Muslim officer in SPG and NSG. I do not want to talk about RAW. It is a different thing. How can a National Security Adviser make such a statement? It has appeared in TV and newspapers. So my request to the Government is that it should be controlled. यह एक हिमाकत है। This is nothing but castigating or putting the whole community in one row. These are important points which have to be discussed because a lot of sum has been given to the Department of Personnel also. I hope that the hon. Finance Minister would reply to it positively. I would also hope that he would increase the allocation for the Ministry of Minorities Welfare which has been created by the UPA Government.

श्री सुनील ख़ां (दुर्गापुर) : महोदया, मैं अनुदान मांगें सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन हमारा कुछ रिजर्वेशन भी है। इस रिजर्वेशन के चलते मैं कुछ वादा करता हूं क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, वह सारे सिनेरियो से वाकिफ हैं, जैसे प्राइस राइज है। हमारे देश में सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जो मूल मुद्दा है कि पैट्रोलियम के ऊपर जो 52 प्रतिशत टैक्सेशन है, पर अगर हम उसमें थोड़ा-बहुत टैक्सेशन विदड्रा कर लें तो जो महंगाई बढ़ रही है, वह कम हो जाएगी, उसमें गिरावट आ जाएगी। इसके लिए हमारे माननीय वित्त मंत्री जी कहेंगे कि फिर कहां से हम रैवेन्यू जनरेट करेंगे। रैवेन्यू जेनरेट करने के बहुत सारे तरीके हमारे देश में है। हमारे देश में बहुत ब्लैक मनी है। रिलायंस के माफिक अगर कोई कंपनी है, यदि पैट्रोलियम पर ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार की मदद से आ जाता है तो उस पर कराधान करके थोड़ा ज्यादा रेवेन्यू सरकार अर्न कर सकती है। इसी तरह भी हो सकता है कि जिस आदमी के पास दो गाड़ियां हैं, उन पर हम इंकम टैक्स लागू कर सकते हैं लेकिन हम लागू नहीं करते हैं। अगर हम यहां से रैवेन्यू जनरेट करेंगे तो आम आदमी के लिए राहत मिल जाएगी।

जैसे गरीब आदमी के लिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वह सिस्टम सारे राज्यों में है। लेकिन यह सिस्टम अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है। उसको सरकार अच्छे से देखे, इसके लिए हम मांग कर रहे हैं। फिर सुसाइड को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अभी हमने पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार किया है। हमारे यहां चावल की क्राप ज्यादा हो गई तो हमने क्राप का डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। स्वामिनाथन कमेटी की रिपोर्ट जिस प्रकार से आई है, उसे उसी प्रकार लागू करना चाहिए और ब्याज दर सात प्रतिशत नहीं, चार प्रतिशत करनी चाहिए। अगर हम बैंक को किराया देते हैं, तो दर चार प्रतिशत कीजिए। इससे किसानों को राहत

मिलेगी। हर जिले में एक सायल टैस्टिंग सैन्टर होना चाहिए जो जांच करके किसानों को बताए कि वहां की मिट्टी में कौन सी पैदावार अच्छी होगी। हमारे कामर्शियल बैंक ज्यादा ऋण किसानों को नहीं देते हैं। इसलिए यह भी तय होना चाहिए कि बैंकों से कितना लोन किसानों को मिलेगा।

बीज के क्षेत्र में तो हमने बहुराट्रीय कंपनी मॉनसैन्टो को बंगाल में घुसने नहीं दिया। वह कंपनी जिस राज्य में भी गई, वहां ज्यादा से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए हमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ की एन्ट्री को बंद कर देना चाहिए, जिससे अपने देशी सीड स्टोर्स से किसान बीज ले सके।

रूरल इंप्लायमैंट गारंटी स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन जो एग्रीकल्चरल लेबर है, उसे वहां काम जरूर मिल रहा है लेकिन पढ़े लिखे लोगों को इससे कोई राहत नहीं मिलती है। रूरल इंप्लायमैंट गारंटी स्कीम में आप कैसे पढ़े लिखे लोगों को काम दिला सकते हैं, इस संबंध में भी कोई योजना बननी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान एक अच्छी योजना है। अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहां कई दिनों तक धरने पर बैठे थे। उन्हें आपको राहत देनी चाहिए। उनमें 3000 और 2000 वर्कर्स और लेबर हैं। अगले बजट में आप उनको थर्ड और फोर्थ ग्रेड इंप्लाइज़ बना दीजिए क्योंकि वे छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये समाज की कली है। उनको हम फूल नहीं बना पाएंगे तो कैसे समाज बनेगा? इनकी प्राइमरी एजुकेशन पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, सरकार ने वायदा किया था कि 12 राज्यों में एम्स के स्तर के अस्पताल बनाए जाएंगे। यह वायदा केवल वायदा ही न रहे, बल्कि उसे पूरा किया जाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए इन अस्पतालों का निर्माण शीघ्र कराया जाए। इसके अलावा कई उद्योग सरकार ने बंद कर दिए। बीओजीएल आपने बंद कर दिया, जहां 188 श्रमिक हैं। वहां आपने पांचवां पे कमीशन भी लागू नहीं किया, फिर कहते हैं कि रिटायरमैंट की उम्र 58 साल होनी चाहिए। जब पब्लिक सैक्टर में रिटायरमैंट की उम्र 60 साल है तो उनको भी वही सुविधा दीजिए। आरसीआई में छः-सात आदमी हैं, उन्को भी वीआरएस नहीं मिला। एचएससीएल की भारत के अंदर जितनी यूनिट्स हैं, वहां कर्मचारियों को सैलेरीज़ नहीं मिल रही हैं। मेरा निवेदन है कि उन्हें आप सैलेरीज़ दीजिए। जो असंगठित शिल्प श्रमिक हैं, ईंट-भट्ठे के श्रमिक हैं, जो बीड़ी बनाते हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, मिट्टी का काम करने वाले मज़दूर हैं, जो मकान बनाते हैं, उनके लिए आप ऐसी योजना बनाएं कि जब वे 60 साल के हो जाएं तो उसके बाद उन्हें पेंशन मिल सके। हिन्दुस्तान केबल्स को आप बंद कर दीजिए, अथ वा एमटीएनएल या बीएसएनएल उसे टेकओवर कर ले। इससे आपको डिसइनवैस्टमैंट नहीं करना पड़ेगा। बर्न स्टैन्डर्ड एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे देश में है। अगर उसे रिवाइवल पैकेज नहीं देंगे, तो हमारे लिए सही नहीं होगा।

मुझे और भी बातें कहनी थीं, किन्तु समय की कमी है। जैसे गंगा नदी और दामोदर नदी में भारी इरोज़न हो रहा है। अगर उसे हम ठीक नहीं करेंगे तो उनमें जल भरने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हम वित्त मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इन् बातों पर ध्यान दें। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

अभी पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से सम्मानित सदस्यों के सुझाव आए। माननीय मंत्री जी 47,868 करोड़ रुपये की डिमांड्ज़ लेकर इस सदन में आए हैं। वैसे देखा जाए और पूरे भारतर्वा की आधारभूत संरचना की तरफ अगर नजर डालें तो आज आम आदमी को शुद्ध हवा, पानी और स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिए। अगर परिवहन क्षेत्र में देखा जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए तो यह क्षेत्र विकास से काफी उपेक्षित रहा है। वैसे सदन में जितने भी हमारे पक्ष एवं विपक्ष के सम्मानित सदस्य हैं, वे आईटी विलेज बनाने की दिशा में रूचि लेते है और सदन में बराबर जिक्र करते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं - जैसे पानी, सड़क एवं दैनिक जीवन में उपभोग की तमाम वस्तुएं, वे बहुत महंगी हो गई हैं, जिन पर अभी पक्ष एवं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की - यहां तक कि दैनिक उपभोग की वस्तुएं आज आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं।

सभापति महोदया,माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भााण में कहा था कि कर-चोरों से सख्ती से निबटने की जरूरत है, तभी हमारा राजस्व बढ़ेगा, लेकिन यह देखा गया है कि महंगी खरीदारी तमाम लोग करते हैं, कहीं पर एक-एक व्यक्ति के पास चार-चार, पांच-पांच, छ:-छ:, एवं सात-सात गाड़ियां हैं और कहीं किसी व्यक्ति के पास एक स्कूटर भी नहीं है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : शैलेन्द्र कुमार जी, यह सप्लीमेंट्री बजट है। आप अच्छा बोल रहे हैं। इस पर आप अपने प्वाइंट्स दे दीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने एक तरफ बुनियादी ढांचे में तीन लाख बीस हजार करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है और दूसरी तरफ हवाई अड्डों को आधुनिक बनाने पर 40 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है, यह ठीक है, लेकिन सरकार की आर्थिक नीतियां विफल रही हैं, खासकर हमारी खाद्यान्न नीति नाकामी की ओर रही है। इन नीतियों के कारण खाद्यान्न और कृाि के क्षेत्र में बहुत संकट आया है। हमारे बहुत से किसानों ने आत्महत्या की है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, इसी कारण महंगाई भी दो सालों में बहुत बढ़ी है। देश के औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है, हमारी उत्पादन क्षमता कम होने के कारण विकास में भी कमी आई है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया :आप सुझाव दीजिए, आप क्या चाहते हैं?

श्री शैलेन्द्र कुमार : पिछड़े क्षेत्रों के विकास और रोजगार गारंटी की जो बात कही गई है, उसे हमें देखने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो तमाम हिन्दीभाी राज्य हैं, उन्होंने बराबर सदन में मांग की है कि उन्हें स्पेशल पैकेज दिया जाए ताकि उनका ि वकास हो सके। उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने बराबर मांग की थी, चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर वहां का ि वकास नहीं होगा तो पूरे देश का विकास नहीं हो सकता।

सभापति महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो सप्लीमेंट्री बजट की मांग की है, उसका मैं समर्थन करता हूं और मैंने जो प्वाइंट्स यहां रखे हैं, उन पर विशेा ध्यान देने की जरूरत है।

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Madam Chairperson, this country needs good economists. We are having Shri P. Chidambaram as Finance Minister who is one of the good economists, along with Dr. Manmohan Singh. But it seems that having too many good economists are not good for a country like India.

I have gone through the Supplementary Demands for Grants thoroughly. I find that even for good economists, the subject of "geography" is very important. In this Supplementary Demands for Grants, geography is missing. I would like to draw the attention of the hon. Minister to a fact. In this country there is a place called "North-East"! I really appreciate that he has given Rs. 550 crore for Special Accelerated Road Development Project for that area. This is a good gesture. In this Supplementary Demands for Grants, I was looking for Golden Quadrilateral project and the river linking project. But these schemes did not find a place in this Supplementary Demands for Grants. I was looking for correction of tax structures. But it is also not available in the Supplementary Demands for Grants[v19].

Madam, I have got a few points.

The hon. Minister of Finance, Shri P. Chidambaram, could look towards the East. The UPA Government has an agenda: "Look East Policy'. If the hon. Minister of Finance could have included

the Look East Policy in these Supplementary Demands for Grants for border trades from the North-Eastern States towards the South-East Asians and towards the Chinese border, then it could have been a good development source for the North-Eastern States.

I was looking for one important thing. Madam, you are from Delhi. You would not be able to know the only State in this country where there is no railway line and where there is no airport is the Arunachal Pradesh State. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : But I go everywhere.

… (*Interruptions*)

SHRI TAPIR GAO : That is why, in this august House, once I called it as a modern Kalapani. Therefore, I was looking for some schemes for this area in these Supplementary Demands, but it has not been mentioned. So, I would request the hon. Minister of Finance to look into it.

Madam, there is one more very important which I would like to highlight here. Madam, as you know, in the Ministry, the DONER Department is there. But under this DONER Department, there is no budgetary provision. The DONER Department's all budgetary provisions are under national pool and it is under the mercy of the hon. Minister of Finance. But one very surprising thing is going on for the North-East. This year, under national pool, the Minister of Finance had allotted Rs. 700 crore for the North-East. Out of which, Rs. 100 crore is allotted for the Bodo Territorial Council (BTC) for which the fund was supposed to be from the Ministry of Home Affairs. … (*Interruptions*) मैडम, हम इतनी दूर से आए हैं, कृपया दो मिनट तो बोलने दीजिए।

I would like to point out about one more important thing, namely, Sarva Shiksha Abhiyan (SSA). I have seen in the Demands for Grants under the Ministry of HRD, a sum of Rs. 92 crore are deducted from the DONER Ministry's non-lapseable Central Pool. It is an injustice to the people of the North East. Again, on top of that, North East Council is there. Now, the NECs are being directed to spend the money for Indo-Bangla fencing. This is a national project. So, all the national projects should not be deducted from the DONER Department and the NEC. This is a great harm to the people of the North-Eastern Region.

Madam, we have got a major railway-cum-road bridge in Dibrugarh which is known as Bogee Bil Bridge. I was looking the point there, but it is missing here. This project was supposed to be made as a national project of this country, but it has not been mentioned. Therefore, I would like to inform the hon. Minister of Finance that to be a good economist, knowledge of geography of the country is also necessary; otherwise regional imbalance will be generated from such financial arrangement.

So, next time I will support the Supplementary Demands for Grants (General). This time I am opposing it because we have got no funds in these budgetary provisions.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Madam, I want to suggest some points to the hon. Minster of Finance. As far as this price rise in respect of diesel and petrol is concerned, during the last two years, it has been increased six times. It has a cascading effect on other essential commodities and in other areas also. This Government has reduced the excise and customs duties. Even that reduction is also not sufficient. So, you have to think further reduction of these taxes and also to convene the meeting of the Chief Minsiters. Even the Chief Ministers also told the media that due to this crude oil barrel hike and the petroleum product hikes, the prices of essential commodities are increasing[R20].

They are talking like this, but they are not reducing sales tax in their own State. That is why, the burden is falling on the common man.

I would like to mention one thing about the National Calamity Contingency Fund. In the Budget Speech, the hon. Finance Minister stated:

> "The Planning Commission will draw up a programme for rebuilding the damaged infrastructure and I wish to assure the House that the Government will provide the money for rehabilitation and reconstruction."

Last year, till 31st March, 2006, the total money released from CRF and NCCF was Rs. 5,145 crore. Even under the NCCF, the amounts released to States are very meagre. That is not sufficient to meet the challenges faced by State Governments because every year, States have to meet challenges like flood, drought etc. So, I would like to suggest to the Government that they should provide more money and give thousands of crores to CRF and NCCF. Then only the Government of India will be able to provide enough assistance to State Governments.

Then, the Accelerated Irrigation Benefit Programme was started when the present Finance Minister was the then Finance Minister in 1996 in the United Front Government, but the guidelines have to be changed now. We have to provide 50 per cent of the money as grant to State Governments. Under the present scheme of things, the Government of India is giving only the minimum amount as grant and they are giving the remaining part as loan. The Government has to give more freedom to State Governments to choose as to which project will be completed first and which project will be completed later. If you put restriction on them by saying that the second instalment will be released only when they complete the project, it is not correct. Therefore, the guidelines for allocation of money under the AIBP should be changed.

Sir, in the industry, manufacturing and services sectors are doing very well. Ultimately we have to achieve the targeted growth rate of 8 per cent of the GDP. In future we have to achieve 10 per cent growth rate. If the agriculture sector grows by 4 per cent, then only we can achieve 10 per cent growth

rate. So, the Government should give priority to agriculture. Many farmers are committing suicides in various parts of our country. The hon. Finance Minister and the Prime Minister have announced a very good relief package for the farmers of Maharashtra in which 6 districts of that State will be fully covered. If this kind of relief package is implemented in Andhra Pradesh, it will cover 16 districts.

MADAM CHAIRMAN : Mr. Yerrannaidu, time is very short. You please give only points now.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Madam, I will take only two or three minutes more.

Our State Andhra Pradesh is reeling under floods now. The Government has announced waiver of loan, waiver of penal interest, rescheduling of loan etc. If you sanction the relief package as early as possible, it will be better. Every year we are facing drought and flood situation in our State. If this scheme is implemented it will cover 16 districts of our State, our State will get money under so many heads and the farmers will be very happy.

Then, as far as crop insurance is concerned, last time the Agriculture Minister made an announcement on the floor of the House. At that time, the entire House, cutting across party lines, demanded that the National Agricultural Insurance Policy should be implemented through village panchayats. Then, only the farmers will get the benefit. Even if the *mandal* is taken as the unit, the affected farmers will not get the benefit under the National Agricultural Insurance Policy. This is under the consideration of the Government and the Government is thinking of implementing this policy only from this Khariff season.

Finally, I would like to make a very important suggestion. The Government of India should take immediate measures to interlink all major rivers of our country. If this is done, many problems will be solved. The Golden Quadrilateral Highway Project was started by the previous Government. Everybody is happy about it. The present Government is also continuing that project. By interlinking of rivers, we can avoid flood, we can avoid drought, we can provide employment to unemployed people and we can also generate power which we can provide at a cheaper rate to our farmers[k21].

15.00 hrs.

How [Rs22]many benefits accrue out of this? So, the Government will have to think of inter-linking of rivers. That is the most important thing for any Government. Everybody has the planning but it is not being implemented at the ground level. So, if you implement these things with courage then so many problems will be solved in the country. We can provide cheap power, we can provide employment. Lakhs of people will get employment by these schemes as everywhere the works are going on. They need not give more money under the National Rural Employment Guarantee Scheme. Now, we are providing a sum of Rs.30,000 crore under the National Rural Employment Guarantee Scheme. If you put this money for the inter-linking of rivers, you can excavate canals, you can construct so many things and by that the people will get employment. So, you will have to think of all these things. Before the end of this Financial Year, the hon. Finance Minister has again come for

Supplementary Demands for Grants. So with all these suggestions, I support the Supplementary Demands for Grants.

SHRI GIRIDHAR GAMANG (KORAPUT): Madam, I have only two-three points. There is a controversy being raised on the basis of some news in Orissa that the Government of India is winding up the KBK Scheme. That was stated by the hon. Finance Minister. I think, that is not correct.

Madam, the KBK was started with an objective to provide loan with the State Government Fund at the initial stage. Then, a Special Central Assistance was provided in 1998-99. Now, a Central assistance of Rs.250 crore is being provided every year. This is a long-term action plan and not a short-term action plan. If it is above five years, it is considered as a long-term plan. I hope the hon. Finance Minister will clarify this position of the Government of India so that it should not give a wrong message to the people.

Madam, the floods which have occurred in KBK as well as hilly areas will have to be assessed scientifically. Unless, a Special Central Assistance, is given to the districts, like Kalahandi, Koraput and all these hilly areas, where they have suffered a heavy loss and damage, it will be very difficult for the people to come out of this. Unless this Rs.100 crore package is given, how can roads, bridges, culverts, etc. be repaired? Although it is an annual feature for coastal belt, in hilly areas this type of damage has occurred for the first time.

Madam, my friends were raising an issue regarding disinvestment of PPL. The process of disinvestment occurred during the NDA regime. It was done for almost all the projects through strategic sale. But the UPA Government is yet to go for this type of sale of any industry. The disinvestment of NALCO to the extent of ten per cent, which was proposed, has been kept on hold by the UPA Government. I had filed a PIL in the Orissa High Court against this decision of the NDA Government. Now it is *sub judice*. Therefore, the Government of India cannot go for the sale of NALCO. All these things will have to be clarified by the hon. Finance Minister, particularly, on the issue of KBK so that controversial issues like KBK should not be raised.

डॉ. रामकृण कुसमरिया (खजुराहो) : सभापति महोदया, मैं अनुपूरक अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जिस इलाके से आया हूं, उस इलाके में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना लोगू की है, मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन प्रैक्टीकली फील्ड में पंचों और सरपंचों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, तब उसका ज्यादा लाभ होगा। दूसरे, केवल 100 दिन काम करने के बाद यदि और काम की जरूरत है तो उसे भी और आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : डॉ. कुसुमरिया जी, आप सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर अपने सुझाव दे दीजिए जो आप सरकार से चाहते हैं।

डॉ. रामकृण कुसमरिया : अब मंहगाई बढ़ गयी है। किसानों द्वारा आत्महत्यायें हो रही हैं। इससे पहले आम बजट में, सत्र के दौरान, इन्होंने जो वायदे किए थे, वे एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। लोगों को आपने बजट में जो राहत दी थीं, वह लोगों को आज भी समझ में नहीं आ रही हैं। विकास के काम भी शुरू नहीं हो रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत जो हमारे यहां केन और बेतवा का एमओयू खजुराहो से साइन हुआ है, उसमें भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पर भी आपकी निगाह नहीं है। जो राट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, जैसे झांसी से खजुराहो राजमार्ग आगे-आगे बन रहे हैं और पीछे-पीछे उखड़ रहे हैं, इस ओर ध्यान देने की आ वश्यकता है। आज किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं। मंहगाई से लोग त्रस्त हैं।

सभापति महोदया : आपके दो मिनट हो चुके हैं, आप अपने सुझाव दीजिए।

डॉ. रामकृण कुसमरिया : राट्रीय राजमार्ग के काम में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। मैं कहना चाहता हूं कि -

"जिन्हें रोटी की जरूरत थी, उन्हें रोटी न मिली,

जिन्हें बोटी की जरूरत थी, बोटी न मिली।

तुम्हारी सियासी तकरीरों के चलते

नंगे को लंगोटी न मिली।"

आज यह हालत मंहगाई की है।...(व्यवधान)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) : इसे धार्मिक लोग पहनते हैं। माननीय सदस्य लंगोटी के बारे में गलत बात बोल रहे हैं। लंगोटी धार्मिक लोग, अच्छे लोग, सब लोग पहनते हैं, यह गलत बात बोल रहे हैं।

डॉ. रामकृण कुसमरिया : वह नहीं मिल रही है।

"अगर यही हालत आपकी चलती रही,

जो जोर और जुल्म के होने से शुरू होती है,

किसी गरीब के रोने से शुरू होती है,

भस्म होते हैं तख्ते ताउस,

जब आग किसी कोने से शुरू होती है।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री छेवांग थुपस्तन (लद्दाख) : महोदया, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फार ग्रांट्स पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लद्दाख जैसे सुदूर क्षेत्र, ट्रांस हिमालयन स्टेट्स में जितने क्षेत्र हैं, उनके साथ फंड्स के एलोकेशन और आवंटन में नाइंसाफी हो रही हैं, इस बारे में मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा।

आपको मालूम है, यहां वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह जानते हैं कि जितने भी मंत्रालय भारत सरकार के हैं, अगर उनकी कार्य पद्धति का कोई मापदंड रखना हो या उनकी सफलता के बारे में आपको कोई जायजा लेना हो, तो मैं समझता हूं कि लद्दाख जैसे क्षेत्र में जाकर इसका जायजा लेना चाहिए, ताकि सही तरीके से हम पता लगा सकें कि जो मंत्रालय की स्कीम्स हैं, जो उनके द्वारा चलाए गए प्रोग्राम्स हैं, वे किस हद

तक देश में सफलता या असफलता के साथ चल रहे हैं। यदि सही तरीके से इन्हीं आइडल क्षेत्रों में जाकर देखा जाए, तो उससे हमें कुछ जायजा मिल सकता है। मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जितने भी लद्दाख जैसे ट्रांस हिमालयन, हिमालय के उस पार स्थित हमारे स्टेट्स हैं, उनके साथ इस लिहाज से नाइंसाफी हो रही है, जितने भी फंड्स स्टेट को आवंटित किए जाते हैं, उनकी उचित मात्रा इन क्षेत्रों को नहीं मिल पाती है। इसका कारण यह है कि फंड्स एलोकेशन में पापुलेशन को मेन बेसिस बनाया जाता है।

15.10 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair)

मेरे विचार से इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्ट्रैटजिक बोर्डर एरियाज में स्थित हमारे इन क्षेत्रों का जब जिक्र आता है, उनकी इकानामिक डैवलेपमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यह जरूरी है कि फंड्स एलोकेशन के जो नार्म्स हैं, उनके बारे में भी रिव्यू किया जाए।

वित्त मंत्री जी शायद मुझसे एग्री करेंगे कि जम्मू कश्मीर का काफी क्षेत्र मेरी कौन्सटीटूएंसी में पड़ता है, और लद्दाख, जो मेरी कौन्सटीटूएंसी है, दोनों को मिलाकर दो-तिहाई क्षेत्रफल के लिहाज से बडा है, लेकिन जब फंड्स एलोकशन की बात आती है, क्योंकि पौपुलेशन को मेन बेसिज़ बनाकर आबंटन होता है, तब उसके साथ उपेक्षा होती है। हमें जितना एलोकेशन मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता। यही कारण है कि वह इलाका पहले से भी ज्यादा पिछड़ता नज़र आएगा।

मैं वित्त मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जहां तक ट्रांस-हिमालयन क्षेत्र या हिल स्टेट्स की बात है, बाकी सदस्यों ने भी इस बात को उठाया है कि वहां के एलोकेशन के मापदंड में तब्दीली लाने की जरूरत है और पौपुलेशन के साथ-साथ एरिया को भी कंसीडर किया जाना बहुत जरूरी है, अन्यथा उन क्षेत्रों के साथ कभी जस्टिस नहीं हो पाएगा। ऐसे क्षेत्र क्लाइमेटीकली बहुत ही मुश्किल होते हैं, वहां वर्किंग सीज़न लिमिटेड होता है और जितना फंड मुहैया किया जाता है, उसका उपयोग थोड़े समय में करना बहुत मुश्किल होता है। जितने हमारे मंत्रालय हैं, खासकर रूरल डैवलपमैंट मंत्रालय द्वारा देश के मैनलैंड को लेकर मापदंड बनाया जाता है और ऐसे क्षेत्रों के लिए भी उसी मापदंड को एप्लाई किया जाता है। उसमें तब्दीली लाने की जरूरत है, अन्यथा जो थोड़ा-बहुत फंड हमें मिलता भी है, उसका उपयोग सही प्रकार से नहीं हो पाता क्योंकि वहां वर्किंग सीज़न बहुत कम होता है।...(व्यवधान)सारा कंस्ट्रक्शन मेटीरियल यहां से जाता है। लद्दाख जैसा क्षेत्र सात महीने सड़क मार्ग से कटा रहता है, इसलिए वहां अगले सीज़न के लिए भी कंस्ट्रक्शन मेटीरियल पहले से जमा करना पड़ता है। जब तक उस क्षेत्र के लिए हम अलग से नहीं सोचेंगे, तब तक वह क्षेत्र सुविधाओं से वंचित ही रहेगा।

वित्त मंत्री जी यह भी जानते हैं कि लद्दाख को इन्कम टैक्स से ऐग्ज़ैम्प्ट रखा गया जिसके पीछे खास वजह थी। आज के प्रधान मंत्री जब वित्त मंत्री थे, उनके जमाने में लद्दाख को इन्कम टैक्स से एग्ज़ैम्प्शन दिया गया था। जब पूरे देश में वैट लागू हुआ, उस समय लद्दाख को सेल्स टैक्स में भी छूट थी क्योंकि एक कोशिश हुई थी कि लद्दाख जैसा दूरदराज इलाका भी आर्थिक दृटि से देश के बाकी हिस्सों के बराबर आ पाए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब जम्मू कश्मीर सरकार ने भी वैट रिजीम को मान लिया, देश के और सुदूर क्षेत्र, जैसे अंडमान-निकोबार, वहां सेल्स टैक्स लागू नहीं था, इन्कम टैक्स से बरी था, उन्हें वैट रिजीम से बाहर रखा गया, लेकिन लद्दाख क्षेत्र के साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने इस बारे में वित्त मंत्री, भारत सरकार को लिखा था। उन्होंने कहा कि फाइनैंस मिनिस्टर की एक एम्पावर्ड कमेटी है, जिसकी रिकमैंडेशन आने पर इस बारे में रिव्यू हो सकता है, लेकिन अभी तक इस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं वित्त मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि जब तक लद्दाख की आर्थिक स्थिति देश के दूसरे क्षेत्रों के बराबर नहीं आ पाती, तब तक उसे वैट और सेल्स टैक्स से मुक्त रखा जाए।...(व्यवधान) हमारे सामने उदाहरण हैं किबहुत से क्षेत्रों को वैट रिजीम से ऐग्ज़ैम्प्ट रखा गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं।...(व्यवधान) वित्त मंत्री जी यहां मौजूद हैं। उनके नोटिस में भी है, लेकिन मैं दोबारा उनके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्वाइंट रिकार्ड में आ गया है, अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री छेवांग थुपस्तन : जब लद्दाख में लोगों की डिमांड पर लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल की स्थापना की गई, वहां यूनियन टेरीटरी स्टेटस की मांग हो रही थी, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें आर्थिक दृटि से सक्षम बनाने के लिए वहां रीजनल ऑटोनोमस काउंसिल देने की बात की है। अब तक भारत सरकार की तरफ से कोई एडीशनल एलोकेशन नहीं हुआ, प्रधान मंत्री जी ने सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 40 करोड़ रुपये एनाउंस किए, वही मिले हैं, जबकि दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को भारत सरकार की तरफ से सप्लीमैंट्री प्लान के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन लद्दाख को बिल्कुल नहीं मिला है। एलोकेशन के मामले में लद्दाख को अभी तक सिर्फ जम्मू-कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर देखा जाता है, जो नाइंसाफी है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहता हूं कि वे इस बारे में सोचें और लद्दाख के लिए उचित धन की व्यवस्था करें।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to the very large number of hon. Members, who have taken the trouble to participate in this debate on Supplementary Demands for Grants (General). Naturally, the debate has been wide ranging like any debate on Demands for Grants will be.

Many hon. Members, who raised questions pertaining to their States, are not here. So, while I would be quite happy to answer each of their questions, and reply to the points made by them, I think, having regard to the circumstances in which we are concluding this debate, let me be very brief and only touch upon the main points, which are more general in nature.

Sir, yesterday, we announced the fact that the CCEA has approved the Backward Region Grants Fund. Let me make it very clear that 250 districts have been selected. The RSVY has been subsumed under the BRGF. Therefore, Bihar Package will be implemented as part of the BRGF, and all the eight districts of KBK are included under the BRGF. Therefore, there need be no apprehension. If you wish to have the details of the scheme, please write to the Minister for Rural Development; he will be happy to furnish the details of the scheme; or write to the Minister of Panchayati Raj, which is the Ministry now in charge of implementing the BRGF.

Sir, as far as the prices are concerned, we have already had a rather extensive debate on prices. I have tried to explain ICCL headline inflation is under control. In fact, this week, we are reporting that WPI index has come down from 4.67 to 4.61. As I have said, given the current market conditions, given the rather brisk pace at which the economy is growing, it is perhaps optimistic to expect that headline inflation will be about 4.5 per cent. Headline inflation will be about 4.5 per cent. What is causing problems to the common man and woman is the fact that wheat, pulses and to some extent, sugar have shown an increase in prices. I have already shared with the House the steps that we have taken to moderate the prices of wheat, pulse and sugar. In fact, since 13th of June until today, for over eight weeks, these prices have been stable. I am not saying that they have come down, but they have not risen, which means that the steps that had been announced are having an impact, and when the new sugar comes from 1st of October, imported wheat arrives and the new wheat crop comes from the 1st of January, there will be a further moderation in prices.

We have also explained that last year was a bad procurement year. In pulses, there is an overall shortage; there has always been an overall shortage. We import pulses, which are available in Myanmar. Myanmar also has a shortage. But the steps that we have taken so far have contained prices, but for these three commodities, our daily monitoring reveals that all others are stable or have marginally declined.

Sir, there was some question about funds to the North-East. I have with me figures of release of funds to the North-East since 1998-99[KD23].

I have Statewise figures. We have, since 1998-99 under NLCPR, released nearly Rs.4,000 crore. Money is not a constraint. In fact, monies which are released must be spent in the year in which they are released but if they are not spent in the year in which they are released or spent for the purpose for which they are released, I am afraid the benefits will not flow to the people.

Then issues relating to credit were raised. We have already answered several times through Questions-Answers and through debates. One of the biggest achievements of the UPA Government is that we promised to double agricultural credit in three years, and we have achieved it in two years. Last year we disbursed agricultural credit of Rs.1,67,000 crore but this year, the target was fixed at Rs.1,75,000 crore. But let me say with utmost confidence that we will far exceed the target this year also. Therefore, agricultural credit is flowing.

We have brought down the rate of interest on crop loan to seven per cent. I wish we could do more but please remember that under the previous Government, crop loans were available at between nine and nine-and-a-half per cent. It is the UPA Government which brought it down to seven per cent giving a clear advantage to the farmer up to two and two-and-a-half per cent. It is not for this year alone. Last year, if you remember the Budget, I returned two per cent interest to the farmers who had taken the loan at nine per cent to nine-and-a-half per cent. I returned two per cent.

We are aware of agricultural indebtedness. … (*Interruptions*) I am trying to explain. We are running out of time. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, this is not allowed. Please sit down. This is not the time to seek clarification.

SHRI P. CHIDAMBARAM: The Deputy-Speaker is not allowing you. Please sit down. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why are you wasting the time of the House?

SHRI P. CHIDAMBARAM: You will recall that the Prime Minister expressed his concern about agricultural indebtedness. After a gap of many years', he said, "We will appoint an Experts group to look into agricultural indebtedness." With the Prime Minister's approval, I am happy to announce that

the following Experts group has been appointed to look into the problem of agricultural indebtedness. The Chairman will be Prof. R. Radhakrishna, Director, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai. The other members will be Dr. P.V. Shenoy, former Secretary, Agriculture, Government of India, Dr. Y.S.P. Thorat, Chairman of NABARD and Shri Kanthakumar, retired Chairman and Managing Director, Syndicate Bank. Once this Committee's report comes, we will address the issue of agricultural indebtedness.

Sir, there were some questions about IDPL's revival. The matter is now with the Ministry. It is expected to be submitted to the BRPSE. Once the BRPSE makes its recommendation, it will go to the Cabinet.

There were some questions about Telengana freedom fighters. The Ministry of Home Affairs calls it the Hyderabad Liberation Movement. Sir, 192 State reports are in process. All other cases have been disposed of. Only 192 cases are in process, of this, 174 relate to the Hyderabad Liberation Movement. The Ministry of Home Affairs has indicated that these cases will be processed as quickly as possible.

Since our Government came into office, we have given equity support to the National Backward Classes Finance and Development Corporation. In 2004-05, it was given Rs.18.72 crore. In 2005-06, we gave another Rs.12 crore, and in 2006-07, we have given another Rs.22 crore.

For the National Minority Development Corporation, in 2005-06, we gave Rs.19.60 crore, and in the current year, we are giving Rs.16.47 crore. As and when more funds are required, we shall certainly look into the matter and give support.

There were some concern about the import of pepper and the decline in prices of pepper[m24].

India is not a large player in the international pepper market which means India is not a price-setter. India's production, compared to global production, is not very large. International prices virtually dictate prices everywhere in the world, including in India. The quantity of pepper that is coming from Sri Lanka under the bilateral agreement is not very large, nor is the value very large. In fact, the quantity has declined in the last three years. We do not have the full figures for the last year. In 2003-2004 it was about 4,916 tonnes. In 2004-2005 it was 4,865 tonnes. For 2005-2006 we do not have full figures. But for the first nine months or so it was 4,883 tonnes. The value is about Rs. 35 crore to Rs. 40 crore.

So, it is, perhaps, not possible to reach the conclusion that pepper from Sri Lanka is causing the decline in prices. But I have requested the Ministry of Commerce to look into the matter to see what can be done and if any imports are affecting prices in India.

On the Department of Fertilisers, as I said – and I have said it at many fora - if any two things require subsidy, it is food and fertiliser. The commitment of the UPA Government is that food will be subsidised in this country because there are large number of poor people; and fertiliser will also be

subsidised in this country. There is no question of whittling down food subsidy or fertiliser subsidy. In 2005-2006 the total subsidy to fertiliser was Rs. 18454 crore. That, of course, includes the initial provision and then the supplementary provisions. In 2006-2007 we have already given Rs. 17, 253 crore and today I am asking for another Rs. 1,500 crore. The total comes to Rs. 18,753 crore. If it becomes necessary to further subsidise fertilisers, surely I will come forward to the House and ask for more funds to subsidise fertiliser. Let me repeat. We may want to plug the loopholes in fertiliser subsidy. We may want to have a different system of distributing fertiliser subsidy. But there is no question that in India food and fertiliser have to be subsidised for a long, long time to come.

On the status of Ramagundam unit of Fertiliser Corporation, there is a proposal from a private company for setting up a gas-based urea plant using the existing infrastructure of the Ramagundam unit of FCI. The proposal is under examination.

On the National Institute of Science in Bhubaneswar, the UGC had proposed setting up of four national institutes of science; one of them is in Bhubaneswar. The proposal has to be pursued by the Ministry of Human Resource Development. Regarding the setting up of a centre at Kolkata, the Government has now decided to set up two institutes – one at Kolkata and one at Pune – based on the recommendations of the Scientific Advisory Council to the Prime Minister. An allocation of Rs. 50 crore has been provided in BE 2006-2007. This is a distinct proposal. This has nothing to do with the UGC's proposal. The UGC's proposal is a separate proposal and that has to be pursued with the Ministry of Human Resource Development.

As far as GQ is concerned, I do not know why this controversy has picked up from time to time. The fact remains that of the 5,846 kilometres of Golden Quadrilateral, when the previous Government demitted office, they had completed 48 per cent. I cannot add a kilometre; I cannot subtract a kilometre nor can I, to please my friend, add a per cent or a subtract a per cent. That is a fact - cold, hard fact. Today we have completed 92 per cent. My arithmetic tells me 92 minus 48 is 44 per cent. So, in two years we have completed 44 per cent. We will complete another 4 per cent by the end of the year. By the end of the year we would have completed 96 per cent. For the remaining 4 per cent advertisements have been taken out in all the newspapers saying where the bottleneck is, what is the bottleneck and which stretch. Those bottlenecks have to be cleared[krr25].

I will request my colleague to take Shri Swain to the bottlenecked portions and try to get his help to solve the problem. … (*Interruptions*) You go with him now. He will take you. … (*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Regarding your statistics, I will not ask you anything. It is a very intelligent work. … (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: No. He will take you. … (*Interruptions*) He will take a stand. You please sit. … (*Interruptions*)

Sir, since the AIBP started, 200 projects have been taken up. Unfortunately, AIBP guidelines were diluted from time to time. What is the result? Only 50 projects have been completed, with some

delays. Now, the remaining 150 projects are at various stages of implementation with considerable delay running from one to three years. A Group of Ministers has been constituted under the Minister of Agriculture. This Group has already held a meeting. They will finalise the revised AIBP guidelines and recommend them to the Cabinet. The idea is to complete as quickly as possible the 200 projects which have been taken up rather than spread the money even more thinly by taking many more projects. The funding pattern is that 90 per cent is grant by the Central Government and 10 per cent is loan for Special Category States. For others, the grant element ranges from 20 per cent to 30 per cent. For Andhra Pradesh, the grant element ranges from 24 per cent to 30 per cent.

NREGP is, of course, a programme of the UPA Government and there is a budget provision of Rs. 11,300 crore. So far we have released Rs. 4,375 crore. I have got the State-wise amount of funds released to the States. It is not correct to say that some States ruled by some parties are doing well and other States ruled by other parties are not doing well. That is an unnecessary twist you are giving to the controversy. States are implementing it. This is the first year. Many States are implementing it. Large amounts have been released. The States which have received large amounts so far are Assam, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa and UP. These are the States, but the release also depends upon how many districts of that State have been taken up. Since only 200 districts have been taken up, if in a particular State, more districts have been taken up, obviously the releases will be more, but in a State like Punjab where only one district has been taken up, the release will obviously be little. So, I do not think, you can compare it that way. In terms of number of districts taken up in a State, I think, the funds are flowing. The budgeted amount is available to the States.

Sir, I think, I have answered most of the main questions. I have made a note of all other issues raised by the hon. Members. We shall certainly pass them on to the Ministries concerned to look into them and, if possible, reply to the hon. Members.

With these words, I would request that the Supplementary Demands for Grants be passed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (General) for 2006-2007 to the vote of the House.

The question is:

> "That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Accounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2007, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 3, 5 to 8, 11, 17 to 19, 30, 31, 33, 35, 41, 44 to 48, 52 to 54, 56, 61, 64, 69, 70, 78, 84, 85, 91, 94, 99, 100 and 102 to 105."

The motion was adopted